



BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम

जमीनी स्तर पर उद्यमिता के ज़रिए ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा

25 जुलाई 2026

स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, प्रशिक्षण, फ़ाइनेंस, मेंटरिंग और समुदाय के नेतृत्व वाले संस्थागत सहयोग के ज़रिए ग़ैर कृषि व्यवसायों को मदद देता है। 30 जून, 2026 तक, एसवीईपी ने देश भर में 4.32 लाख ग्रामीण व्यवसायों को मदद पहुँचाई है। इस कार्यक्रम ने सामाजिक समावेश और उद्यमिता के मौकों तक समान पहुँच पर ज़ोर दिया है। लगभग 86% उद्यमी एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और ओबीसी समुदायों से आते हैं। एसएचजी, सीआरपी-ईपी, बैंक लिंकेज और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर एसवीईपी ने अपनी पहुँच बढ़ाई है। एसवीईपी गरीबी कम करने, स्थानीय स्तर पर रोज़गार पैदा करने और ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए एक असरदार ज़मीनी मॉडल के तौर पर उभरा है।

भारत में उद्यम-आधारित ग्रामीण बदलाव

भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम है। यह सरकार की अच्छी नीतियों की मदद से खूब फला-फूला है और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। हालांकि, भारत के ज़्यादातर स्टार्ट-अप इकोसिस्टम शहरी इलाकों में हैं। इसलिए, सरकार ने ग्रामीण इलाकों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इनमें से एक मुख्य पहल है **स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी)**।

2016 में शुरू किया गया एसवीईपी, **दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)** की एक उप-योजना है। यह योजना स्वयं सहायता समूहों और उनके परिवार के सदस्यों को खेती से अलग क्षेत्रों में छोटे उद्यम शुरू करने में मदद करती है। यह आर्थिक मदद, संस्थागत सहयोग, बिज़नेस मैनेजमेंट का प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और बिज़नेस डेवलपमेंट से जुड़ी सेवाएँ देता है। इससे ग्रामीण इलाकों में टिकाऊ आजीविका और स्वरोज़गार के मौके बढ़ते हैं।

एसवीईपी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच और सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद करता है। इसका मुख्य मकसद लंबे समय तक आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर सामाजिक लाभ हासिल करना रहा है। एसवीईपी की एक खास बात यह है कि इसमें स्थानीय स्तर पर उद्यमों को फंड देने और मदद करने के लिए फ़ैसले समुदायिक स्तर पर लिए जाते हैं।



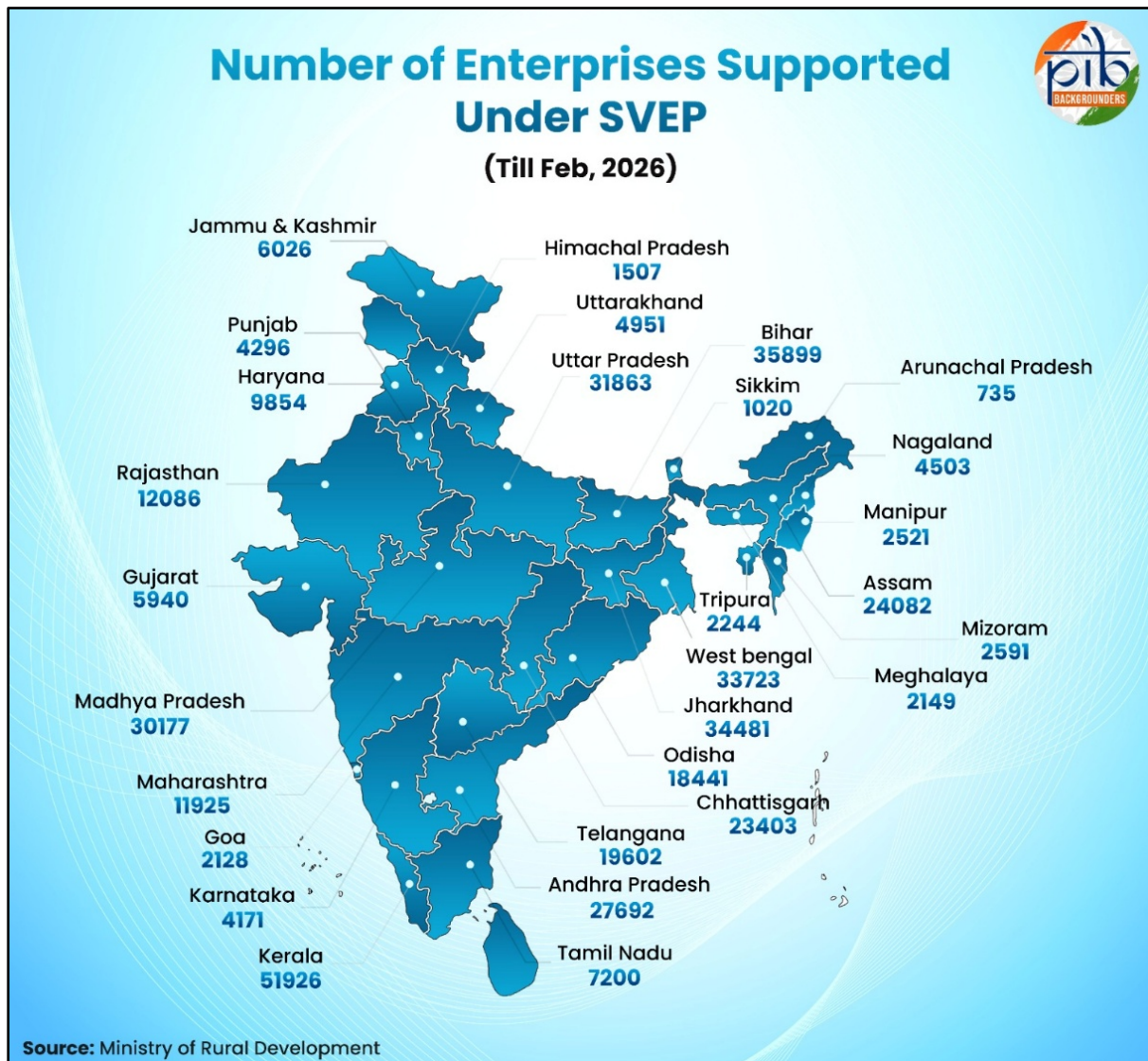
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) दुनिया की सबसे बड़ी आजीविका पहलों में से एक है। यह ग्रामीण गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं को स्वयं-सहायता समूहों में संगठित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें टिकाऊ आजीविका, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना है। जून 2026 के मध्य तक, डीएवाई-एनआरएलएम के तहत 10.29 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को एसएचजी में संगठित किया जा चुका है।

पूरे भारत में ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना

एसवीईपी ने एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें महिलाओं, वंचित समुदायों और कम पढ़े-लिखे लोगों को सहयोग देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। अपनी शुरुआत से लेकर 15 जून 2026 तक, इस कार्यक्रम

ने 4.32 लाख से अधिक ग्रामीण उद्यमों को सहयोग दिया है। असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक संख्या में उद्यमों को सहयोग मिला है।



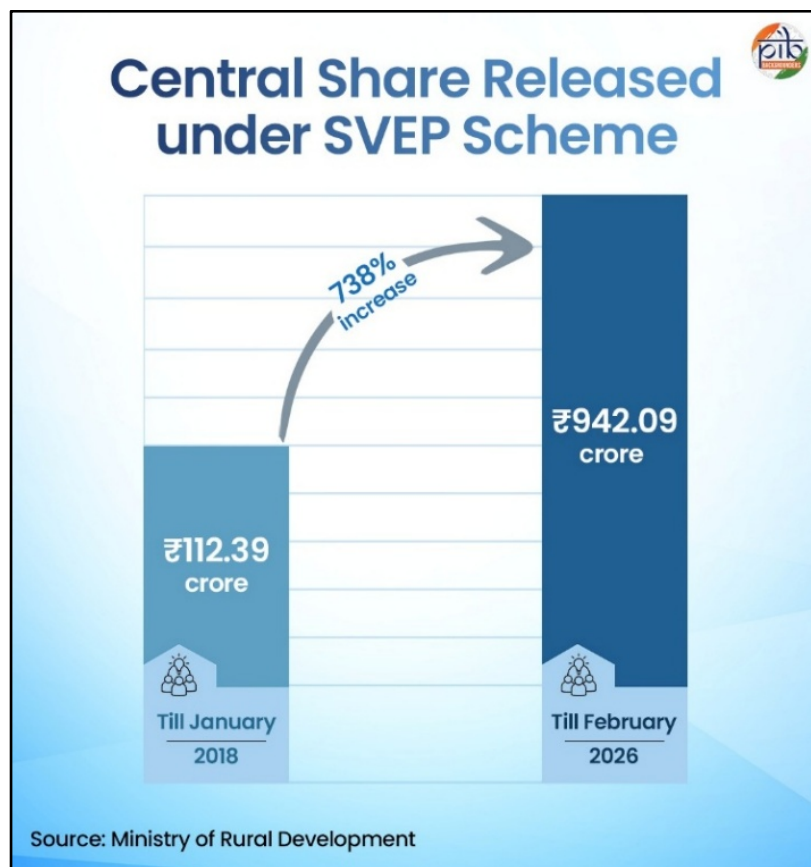
एसएचजी सदस्य से ग्रामीण बिज़नेस लीडर तक का सफ़र

महाराष्ट्र के जहानपुर की रहने वाली भाग्यश्री लोंढे ने 2014 में एक एसएचजी से जुड़कर अपना सफर शुरू किया। एसएचजी और ग्राम संगठन (वीओ) की गतिविधियों में हिस्सा लेने से नेतृत्व और व्यापार से जुड़ा उनका कौशल बेहतर हुआ। उन्होंने मसाला, पापड़ और अचार बनाकर अपना व्यापार शुरू किया। एसवीईपी के तहत ₹45,000 के **कम्युनिटी एंटरप्राइज़ फंड लोन** की मदद से, उन्होंने स्थानीय स्तर पर मिलने वाले कच्चे माल का इस्तेमाल करके अपना उत्पादन बढ़ाया। उनके व्यापार प्रयासों को महालक्ष्मी सरस 2019-20 में पहचान मिली, जहाँ उन्होंने दस दिनों में ₹5 लाख की कमाई की।

सीखने और आगे बढ़ने की चाहत ने उन्हें अपने व्यापार के ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने में मदद की। अपना व्यापार संभालते हुए उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। एनआरएलएम और

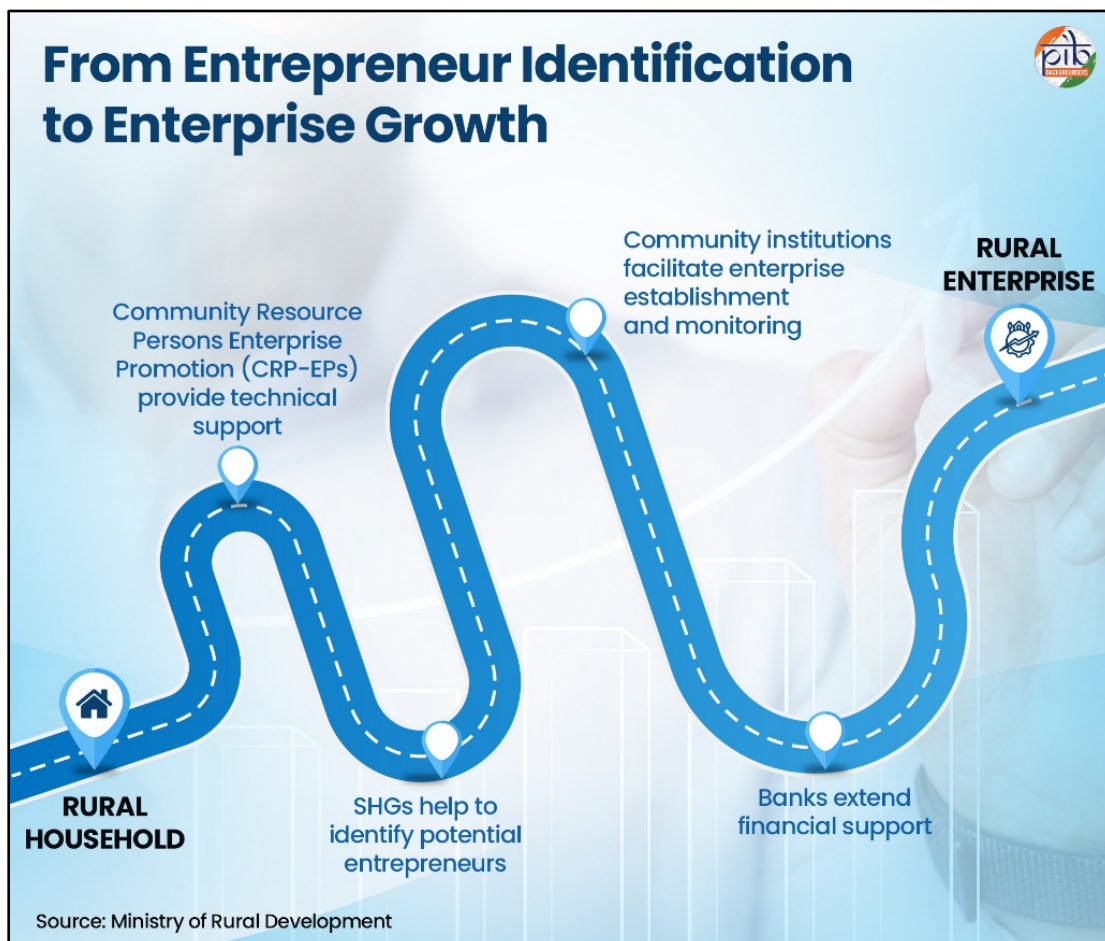
कृषि विज्ञान केंद्र से मिले प्रशिक्षण ने उनकी व्यापार की समझ और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाया। नतीजतन, उनके व्यापार में रोज़ाना बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, जिससे नियमित कमाई हुई और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हुए। उनका सफर दिखाता है कि कैसे उद्यमिता, लगातार सीखते रहने और संस्थागत सहयोग से **महत्वाकांक्षी महिलाएं सफल बिज़नेस लीडर** बन सकती हैं।

एसवीईपी के लगातार विस्तार को समर्थन देने के लिए, सरकार ने फरवरी 2026 तक कुल **₹942.09 करोड़** का केंद्रीय हिस्सा जारी किया है। यह 2016 में कार्यक्रम शुरू होने और जनवरी 2018 के बीच जारी किए गए कुल ₹112.39 करोड़ से लगभग **738% ज़्यादा** है।



ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने और उनका विस्तार करने का रोडमैप

एसवीईपी को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के ज़रिए लागू किया जाता है, जिसमें प्रति ब्लॉक ₹6.50 करोड़ का प्रावधान और प्रति उद्यम औसतन ₹27,083 का निवेश शामिल है।



ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर-एंटरप्राइज़ प्रमोशन (बीआरसी-ईपी) कार्यक्रम को लागू करने के लिए मदद करते हैं। प्रशिक्षित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन-एंटरप्राइज़ प्रमोशन (सीआरपी-ईपी) उद्यम को बढ़ावा देने के मामले में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को तकनीकी सहायता देते हैं। बैंक योग्य उद्यमियों को आर्थिक सहायता देते हैं। स्वयं-सहायता समूह और उनके संगठन संभावित उद्यमियों की पहचान करने में मदद करते हैं। सामुदायिक संस्थाएँ उद्यम स्थापित करने में मदद करती हैं और जरूरी सहायता मुहैया कराती हैं। वे कम्युनिटी एंटरप्राइज़ फंड (सीईएफ) के ज़रिए ऋण का प्रबंधन भी करती हैं। सामुदायिक संस्थाएँ उद्यम के प्रदर्शन और विकास की नियमित रूप से निगरानी भी करती हैं। डिजिटल टूल बिज़नेस प्लानिंग, लोन के मूल्यांकन और उद्यम की ट्रेकिंग में मदद करते हैं। यह एकीकृत व्यवस्था प्रभावी कार्यान्वयन और उद्यम विकास सुनिश्चित करती है।

सीआरपी-ईपी को एसआरएलएम और कार्यक्रमों को लागू करने वाली एजेंसियां मिलकर परीक्षण, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण के ज़रिए चुनती हैं। इसमें उन स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनके पास बुनियादी तौर पर व्यापार और गणित की जानकारी होती है। कम से कम 90% सीआरपी-ईपी को एसएचजी परिवारों से चुना जाता है और इस कैडर में कम से कम 60% महिलाएं होती हैं। हर सीआरपी-ईपी 50 उद्यमियों तक को मेंटरिंग, प्रशिक्षण और क्रेडिट दिलाने में मदद करता है।

एसएचजी सदस्य से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सीआरपी-ईपी तक का सफर

उत्तर प्रदेश की पूनम ने सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करके एक सफल सीआरपी-ईपी का मुकाम हासिल किया। एक स्वयं-सहायता समूह से जुड़ने के बाद, उन्हें एसवीईपी के बारे में पता चला और उन्होंने 54 दिन का सीआरपी-ईपी प्रशिक्षण प्रोग्राम पूरा किया। इस प्रशिक्षण ने उन्हें उद्यम को बढ़ावा देने और आजीविका विकसित करने के हुनर सिखाए। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उन्होंने व्यापार की योजना, क्रेडिट दिलाने, बाज़ार से जोड़ने और लगातार मेंटरिंग में मदद करके लगभग 40 उद्यमों को मदद करना शुरू किया। पूनम अपनी आर्थिक आज़ादी का श्रेय एसवीईपी को देती हैं और दूसरों को अपना व्यापार शुरू करने और उसे बढ़ाने में मदद करने के मौके की कद्र करती हैं। उनका सफर दिखाता है कि कैसे समुदाय आधारित संस्थाएं और उद्यमिता के लिए मिलने वाली मदद ग्रामीण आजीविका को मज़बूत कर सकती है और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी को आगे बढ़ा सकती है।

समुदाय की संस्थाएं ज़रूरत, गरीबी की स्थिति और उद्यमिता की क्षमता के आधार पर उद्यमियों की पहचान करती हैं। कारोबार की व्यवहार्यता की जांच के बाद लाभार्थियों को ट्रेनिंग, मेंटरिंग और आर्थिक मदद मिलती है और समुदाय-आधारित संगठन ऋण को मंजूरी देते हैं। इस कार्यक्रम में यह ज़रूरी है कि कम से कम 60% लाभार्थी महिलाएं हों, साथ ही दिव्यांगों और एससी/एसटी/अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।

एसवीईपी की निगरानी राज्य और केंद्र स्तर पर तिमाही समीक्षा और समय-समय पर होने वाले मूल्यांकन के जरिए की जाती है। इसके अलावा, कारोबार के प्रदर्शन, फंड के इस्तेमाल और प्रोग्राम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीय एमआईएस सिस्टम भी है।

ग्रामीण आजीविका और उद्यमिता पर एसवीईपी का असर

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए एसवीईपी का मिड-टर्म मूल्यांकन किया, जिसमें 2019 में बड़े पैमाने पर फील्ड मूल्यांकन किए गए। इस समीक्षा में ग्रामीण कारोबार, आजीविका और सामाजिक समावेश पर प्रोग्राम के असर का आकलन किया गया।

नतीजों से पता चलता है कि आय बढ़ाने, उद्यम विकसित करने और कमज़ोर समुदायों को सशक्त बनाने में अच्छे परिणाम मिले हैं:

- एसवीईपी से मदद पाने वाले 99% उद्यम मुनाफ़े में रहे।
- एसवीईपी उद्यमों का परिवार की कुल आय में 57% योगदान रहा।
- उद्यम से होने वाली औसत मासिक कमाई लगभग ₹39,000 थी।
- विनिर्माण उद्यमों की औसत मासिक कमाई सबसे ज़्यादा ₹47,800 रही।
- 96% उद्यमियों ने बचत बढ़ने की बात कही।

- 75% उद्यम महिलाओं के स्वामित्व या प्रबंधन में थे।

एसवीईपी ने उद्यमियों को उनकी **शुरुआती उम्मीदों से ज़्यादा कमाई** करने में मदद की। फाइनेंस तक बेहतर पहुँच ने उद्यमियों को उद्यम शुरू करने और उन्हें आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया। लगातार मेंटरिंग ने उद्यम प्रबंधन और स्थिरता को मज़बूत किया।

इसके अलावा, एसवीईपी ने महिलाओं और वंचित समुदायों को **पहली पीढ़ी के उद्यमी** बनने के लिए प्रोत्साहित किया। लाभ हासिल करने वालों ने **आत्मविश्वास** और आजीविका की सुरक्षा में सुधार की बात कही। कई परिवारों को **बेहतर शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और साफ-सफाई** की सुविधाएँ मिलीं। उद्यमियों ने बेहतर व्यापार प्रबंधन और वित्तीय कौशल हासिल कीं। **बढ़ी हुई बचत** और दोबारा निवेश ने उद्यम के लंबे समय तक विकास में मदद की। इस कार्यक्रम ने **समुदायों में लाभ पाने वालों का सामाजिक दर्जा** भी बढ़ाया।

कल्याणकारी योजनाओं से उद्यम-आधारित विकास की ओर

एसवीईपी ने यह साबित किया है कि अगर मज़बूत सामुदायिक संस्थाओं का साथ मिले, तो ग्रामीण उद्यमिता समावेशी आर्थिक विकास को तेज़ी से आगे बढ़ा सकती है। महिलाओं, एससी/एसटी समुदायों और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को सशक्त बनाकर, इस कार्यक्रम ने स्थानीय उम्मीदों को टिकाऊ उद्यमों में बदल दिया है। इससे आय बढ़ती है, बचत में बढ़ोतरी होती है और परिवारों की खुशहाली में भी सुधार होता है। सबसे अहम बात यह है कि इसने दिखाया है कि हर गाँव में उद्यमिता की प्रतिभा मौजूद होती है और सही माहौल मिलने पर वह फल-फूल सकती है। जैसे-जैसे भारत एक वैश्विक स्टार्ट-अप हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, एसवीईपी जैसे कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में एक मज़बूत स्टार्ट-अप व्यवस्था की नींव रख रहे हैं। यह रोज़गार पैदा कर रहा है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत कर रहा है और लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए नए अवसर खोल रहा है। कुल मिलाकर, यह एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान दे रहा है।

संदर्भ

ग्रामीण विकास मंत्रालय

<https://svep.nrlm.gov.in/landing>

https://svep.nrlm.gov.in/pdf/Final_Mid_Term_Report.pdf

<https://nrlm.gov.in/dashboardForOuter.do?methodName=dashboard>

https://lakhpatedidi.gov.in/wp-content/uploads/2024/02/SVEP_updated_Master_Circular.pdf

<https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/13/AU2824.pdf?source=pgals>

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1651525®=48&lang=2>

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU3940_Wamd8p.pdf?source=pgals

वाणिज्य मंत्रालय

<https://www.ibef.org/blogs/svep-start-up-village-entrepreneurship-programme>

नागालैंड सरकार

<https://nsrlm.nagaland.gov.in/wp-content/uploads/2020/07/guidelines-CRP-EP.pdf>

पीआईबी बैकग्राउंडर

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2195990®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2267960®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=156719&ModuleId=2®=3&lang=1>

पीआईबी शोध

पीके/केसी/एनएस